

सत्य का ब्रह्मास्त्र

स्वतंत्र बौद्धिकपत्र

सम्पादक-मधुसूदन शर्मा

सह सम्पादक-वृजेश कुमार शर्मा

वर्ष - २ अंक - ५८

सोमवार - २५/०८/२०२५

पृष्ठ - ४

प्रति सोमवार डिजिटल संस्करण

सम्पादकीय

डोनाल्ड ट्रंप की अस्थिर नीतियों की वजह से भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत अधर में लटक गई है। यह अनिश्चितता दोनों में से किसी भी देश के लिए ठीक नहीं। हालांकि अलास्का समिट में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रति ट्रंप का नरम रवैया थोड़ी उम्मीद जरूर जगाता है। ट्रेड डील के लिए अमेरिकी अधिकारियों को इसी 25 तारीख को भारत आना था, लेकिन मौखिक तौर पर बताया गया कि अब यह विजिट नहीं होगी। अभी तक नई तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, जिससे असमंजस बढ़ गया है। पहले माना जा रहा था कि अगस्त आखिर या सितंबर तक दोनों देश एक मिनी डील तक पहुंच जाएंगे। इसके लिए दोनों के बीच कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन अब सबकुछ बिल्कुल थम जाना द्विपक्षीय रिश्तों के लिए सही नहीं। व्यापारिक समझौते में क्यों अड़चन आ रही है, इस बारे में अब सभी को पता है, लेकिन भारत की विंताओं को समझने और बातचीत के जरिये समाधान निकालने के बजाय ट्रंप दबाव की रणनीति अपना रहे हैं। मौजूदा संकट इसलिए भी ज्यादा उलझ गया है, क्योंकि चीन की बढ़ती मनमानी को रोकने के लिए भारत को अहम साझेदार मानने के बावजूद अमेरिका आपसी संबंधों को नुकसान पहुंचाने वाले कदम उठा रहा है। हालांकि इतिहास पर नजर डालें, तो वॉशिंगटन के लिए यह नई बात नहीं लगती। 80 के दशक के आखिर में भी अमेरिका को व्यापार घाटे की विंता सता रही थी और तब उसके निशाने पर जापान था। उसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति को यह अधिकार मिला कि अगर कोई देश अमेरिका के खिलाफ अनुचित व्यापार नीतियां अपनाता है, तो उस पर टैरिफ लगाया जा सके। लेकिन, यह अधिकार मिलने के बाद तत्कालीन ३६ प्रेजिडेंट जॉर्ज एचडब्लू बुश ने जापान के साथ-साथ भारत और अमेरिकी सहयोगियों - यूरोप, दक्षिण कोरिया व ताइवान पर भी एक्स्ट्रा टैक्स लाद दिया। 1989 में जब उन्होंने भारत को टारगेट किया था, तब भी सरकार का यही कहना था कि वह किसी दबाव में नहीं झुकेगी। अमेरिका फिर से इतिहास को दोहरा रहा है।

भारत सौ देशो को इवी निर्यात करेगा,देश के पास तेज धारा को मोड़ने की ताकत,दुनिया को धीमी विकास दर से बाहर निकालेगा देश-पीएम

पीएम ने कहा भारत की प्रगति का आधार रिसर्च और इन्वोवेशन ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अब दुनिया को धीमी विकास दर से बाहर निकालने की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि हम ठहरे हुए पानी में कंकड़ फेंकने वाले लोग नहीं हैं। हम तेज बहती धारा को भी मोड़ने की ताकत रखते हैं। भारत अब समय की धारा को भी दिशा देने की क्षमता रखता है। पीएम ने कहा- भारत अब एक बड़ा माइलस्टोन हासिल करने जा रहा है। देश जल्द ही 100 देशों को इलेक्ट्रिक वाहन निर्यात करेगा। भारत की प्रगति का आधार रिसर्च और इन्वोवेशन है। उन्होंने कहा बाहर (विदेश) से खरीदी



गई रिसर्च सिर्फ जीने भर के लिए काफी है, लेकिन भारत की बड़ी आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकती। केंद्र सरकार ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए लगातार नीतियां और

नए प्लेटफॉर्म बनाए हैं। भारत अब सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, बल्कि मेट्रो कोच, रेल कोच और लोकोमोटिव (रेल इंजन) भी विदेश भेज रहा है। उन्होंने यह बात ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2025 में ये बात कही। पीएम के संबोधन की बड़ी बातें - 2014 से पहले भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात करीब 50,000 करोड़ सालाना था। आज यह बढ़कर ६1.2 लाख करोड़ सालाना हो गया है। जून 2025 में 22 लाख नई नौकरियां इपीएफओ डेटा में दर्ज हुईं, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है।

पाकिस्तान आर्मी चीफ ने अपनी नाकमी स्वीकार की भारत ने मेहनत से फरारी कार जैसी इकोनॉमी बनाई ,पाक की हालत अब भी डम्पर जैसी।

रक्षा मंत्री राजनाथ ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कही ।



रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के श्भारत चमकती मर्सिडीजश वाल बयान पर जवाब दिया। राजनाथ ने कहा- मैं मुनीर के बयान को मजाक (ट्रोल) नहीं, बल्कि उनकी नाकामी स्वीकार करने वाला मानता



हूं। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में राजनाथ सिंह ने कहा - एक देश ने कड़ी मेहनत करके फरारी कार जैसी अर्थव्यवस्था बनाई और दूसरा अब भी डंपर जैसी स्थिति में है तो यह उनकी नाकामी है। मैं आसिम मुनीर के बयान को एक कन्फेशन

संसद भवन की सुरक्षा में चुक दीवार फांदकर कैम्पस में पहुँचा व्यक्ति,2023 मे भी हुई थी ऐसी घटना ।

पीएम मोदी ने नए भवन का उद्घाटन २८ मई २०२८ को किया था ।



संसद भवन की सुरक्षा में गुरुवार को सेंध का मामला सामने आया। एक व्यक्ति दीवार कूदकर संसद भवन में घुस गया और गरुड़ द्वारा तक पहुंच गया। सुरक्षा कर्मियों ने उसे तुरंत दबोच लिया। अब उससे पूछताछ की जा रही है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपी सुबह 6.30 बजे रेलभवन के पास पेड की मदद से दीवार पर चढ़ा और कूदकर अंदर घुसा। हालांकि, घटना के समय संसद में कोई सांसद मौजूद नहीं था। संसद का मानसून सत्र गुरुवार को खत्म हो गया था और राज्यसभा और लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। एक साल पहले 16 अगस्त 2024 को भी एक युवक दोपहर में दीवार फांदकर संसद परिसर में घुस गया था। वहां तैनात सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (सीआईएसएफ) के जवानों ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था।

की तरह देखता हूं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था मलबे से भरे डंप ट्रक जैसी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर हम इस गंभीर चेतावनी के पीछे छिपे ऐतिहासिक संकेत पर ध्यान नहीं देंगे तो यह हमारे लिए चिंता का विषय बन सकता है। अगर हम इस पर ध्यान दें और इसके लिए तैयारी करें तो भारत ऐसी चेतावनियों का करारा जवाब देने में सक्षम है। दरअसल, 11 अगस्त को अमेरिका दौरे पर पहुंचे मुनीर ने भारत को चमकती मर्सिडीज और पाकिस्तान को रेत से भरा डंपर ट्रक कहा था। मुनीर ने कहा था- अगर ट्रक कार से टकराएगा, तो नुकसान किसका होगा?

डॉग लवर्स की याचिका पर सुनवाई कर सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तो को नसबंदी ,टीकाकरण कर छोड़ने को कहा

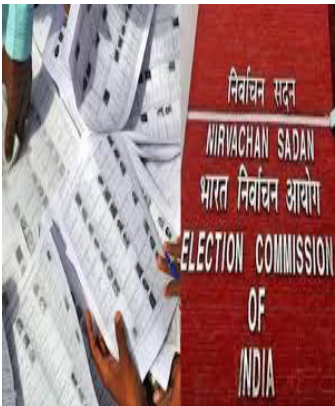
नई दिल्ली में कुत्ते व पशु प्रमियो ने विराध किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में शुक्रवार को कहा कि जिन कुत्तों को पकड़ा जाता है, उनकी नसबंदी और टीकाकरण कर जहां से उठाया है, वहीं वापिस छोड़ दिया जाए। हालांकि, रेबीज से संक्रमित और आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों को शेल्टर होम में ही रखा जाए। कोर्ट ने आदेश दिया कि कुत्तों को पब्लिक प्लेस में खाना न दिया जाए और नगर निगम इसके लिए अलग जगह बनाए। कोर्ट ने कहा कि ये आदेश दिल्ली समेत पूरे देश में लागू होगा। साथ ही याचिका में शामिल

व्यक्ति 25 हजार और 2 लाख रुपए कोर्ट में जमा कराएं। कोर्ट ने 11 अगस्त के 2 जजों की बेंच के उस आदेश को बेहद कठोर बताया, जिसमें सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में दिल्ली-छब्ब के आवासीय क्षेत्रों से हटाकर हमेशा के लिए शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था। जस्टिस विक्रम नाथ,जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की स्पेशल बेंच ने 14 अगस्त को डॉग लवर्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।

बिहार वोटर वेरिफिकेशन में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आधार भी मान्या ।

वोटर्स लिस्ट में नाम जुड़वाने ऑनलाईन भी आवेदन दे सकेंगे।



सुप्रीम कोर्ट में बिहार में चल रही स्पेशल इंटेसिव रिवीजन यानी सर (सामान्य शब्दों में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन) पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह हटाए गए वोटर्स को लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए फिजिकली के अलावा ऑनलाइन आवेदन की अनुमति भी दे। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आधार कार्ड समेत फॉर्म 6 में दिए गए 11 दस्तावेज में से कोई भी जमा किया जा सकता है, इनमें ड्राइविंग लाइसेंस, पासबुक, पानी का बिल जैसे डॉक्यूमेंट शामिल हैं। कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों को मामले पर चुप्पी साधने के लिए भी फटकार लगाई और पूछा कि मतदाताओं की मदद के लिए आप क्या कर रहे हैं। आपको आगे आना चाहिए। अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने पार्टियों से पूछा- आप क्या कर रहे हैं - सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग से कई सवाल पूछे। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा- राजनीतिक दलों की निष्क्रियता हैरान करने वाली है। राज्य की 12 पॉलिटिकल पार्टियों में से यहां मात्र 3 पार्टियां ही कोर्ट में आई हैं। वोटर्स की मदद के लिए आप क्या कर रहे हैं। कोर्ट ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि राजनीतिक दलों के लगभग 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट होने के बावजूद, उनकी ओर से केवल दो आपत्तियां ही आई हैं।

डिजीटल संस्करण

<https://sbpatra.in>

पर उपलब्ध



सत्य का ब्रह्मास्त्र ! स्वतंत्र बौद्धिक पत्र

स्वतंत्र बौद्धिक पत्र (समाचार पत्र)

<https://sbpatra.in>

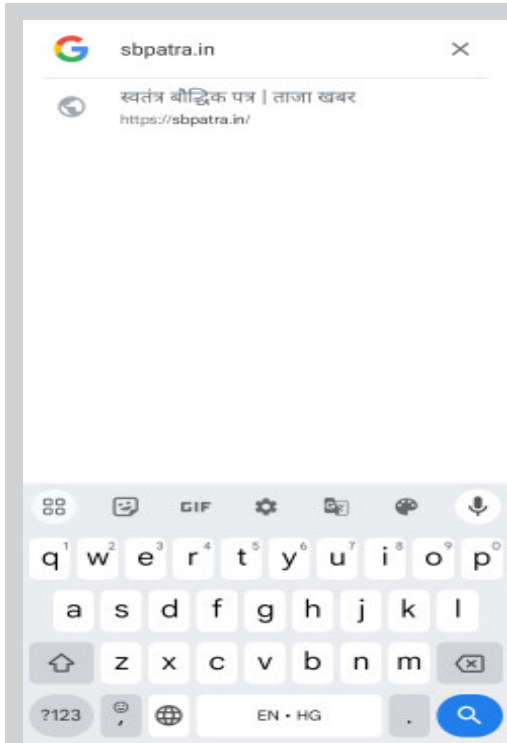
पर डिजिटल संस्करण उपलब्ध



SWATANTRA
BODDDHIK PATRA

खबरों के लिए लॉगिन करें !

<https://sbpatra.in/>



(1)

गुगल सर्च करे - <https://sbpatra.in/>

(2)

होम पेज पर कटेगिरी मे जाए

(3)

ई-पेपर कटेगिरी चुने

(4)

समाचार पत्र आपके सामने क्लिक करे !

निःशुल्क ई-पेपर प्रति सोमवार
को वेब पोर्टल
<https://sbpatra.in/>
से डाउनलोड कर
सकते
है।

स्वतंत्र बौद्धिक पत्र (समाचार पत्र)

<https://sbpatra.in>

पर डिजिटल संस्करण उपलब्ध



भारत को पाँच प्रतिशत डिस्काउन्ट पर तेल उपलब्ध कराने वाले रूस का दावा हमारे कच्चे तेल का कोई विकल्प नहीं।

टैरिफ वॉर मे रूस का कहना है कि हमें विश्वास है कि बाहरी दबाव के कारण ऊर्जा सहयोग जारी रहेगा।



रूस का कहना है कि उसके कच्चे तेल का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि ये बहुत सस्ता है। आज यानी, 20 अगस्त को सीनियर रूसी डिप्लोमेट रोमन बाबुशकिन ने ये बात कही। उन्होंने कहा— रूसी कच्चे तेल पर

भारत को करीब 5: की छूट मिल रही है। भारत इस बात को समझता है कि तेल आपूर्ति को बदलने का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि इससे उसे बहुत ज्यादा मुनाफा हो रहा है। भारत पर अमेरिकी दबाव को भी

रूस ने गलत बताया है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब भारत और अमेरिका के रिश्ते बिगड़ रहे हैं। अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल खरीदने के चलते 50: टैरिफ लगाया है। रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा भारत — बाबुशकिन ने कहा— भारत के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है, लेकिन हमें भारत के साथ अपने रिश्तों पर भरोसा है। हमें विश्वास है कि बाहरी दबाव के बावजूद भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा। उन्होंने ने ये भी कहा कि अगर भारतीय सामान अमेरिकी बाजार में नहीं जा सकते, तो वे रूस की तरफ जा सकते हैं।

भारत पर प्रतिबंध का मकसद रूस पर दबाव बनाना ,इससे यूक्रेन-रूस जंग रोकने में सहायता होगी।

टैरिफ पर व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस



अमेरिका ने रूस पर दबाव बनाने के लिए भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलीन लीविट ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। इससे पहले तक ट्रम्प प्रशासन रूस से तेल लेने पर भारत के खिलाफ की गई आर्थिक कार्रवाई को पैनल्टी या टैरिफ बताता रहा है। ट्रम्प ने भारत पर अब तक कुल 50 टैरिफ लगाने का फैसला किया है। इसमें 25: रेसीप्रोकल यानी जैसे को तैसा टैरिफ और रूस से तेल खरीदने

पर 25: पैनल्टी है। रेसीप्रोकल टैरिफ 7 अगस्त से लागू हो गया है, जबकि पेनल्टी 27 अगस्त से लागू होगी। लीविट के मुताबिक इसका मकसद रूस पर सेकेंडरी प्रेशर डालना है, ताकि वह युद्ध खत्म करने पर मजबूर हो। उन्होंने कहा— व्यापार को हथियार बनाकर भारत-पाक संघर्ष रोकवाने का दावा लीविट ने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत-पाक संघर्ष को रोकने में ट्रम्प ने अहम भूमिका निभाई थी। प्रेस सेक्रेटरी के मुताबिक ट्रम्प ने व्यापार को हथियार की तरह इस्तेमाल कर इस संघर्ष को खत्म कराया। लीविट ने कहा कि ट्रम्प ने अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच पीस डील कराई। साथ ही रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बीच संघर्ष खत्म करने में मदद की। व्हाइट हाउस के मुताबिक, फिलहाल ट्रम्प का सबसे ज्यादा ध्यान रूस-यूक्रेन और इजराइल-हमास जंग को खत्म कराने पर है। ट्रम्प पहले भी कई बार भारत-पाक संघर्ष को खत्म कराने का श्रेय खुद को दे चुके हैं।

श्रीलंका के पुर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे गिरफ्तार

पत्नी के दिक्षांत समाहरो में शामिल होने लंदन गए थे



श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को पुलिस ने सरकारी धन का दुरुपयोग करने के मामले में गिरफ्तार किया है। उन पर आरोप है कि 2023 में राष्ट्रपति रहते हुए वे अपनी पत्नी प्रोफेसर मैत्री विक्रमसिंघे के दीक्षांत समारोह शामिल होने लंदन गए थे। पुलिस का कहना है कि लंदन में उनकी कोई आधिकारिक यात्रा नहीं थी, फिर भी इसे सरकारी खर्च पर किया गया। इस यात्रा में 10 लोगों का ग्रुप शामिल था और करीब 1.69 करोड़ रुपए खर्च किया गया। उस समय विक्रमसिंघे क्यूबा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर थे, जिसके बाद वे निजी यात्रा के लिए ब्रिटेन चले गए थे। इसके अलावा उन पर अपने पर्सनल बॉडीगार्ड को भी सरकारी खजाने से सैलरी देने का आरोप है।

इजराइल ने गाजा सिटी को राफा शहर की तरह मलबे में बदलने की दी धमकी।

इजराइल ने जंग रोकने के लिए पाँच शर्तें रखीं

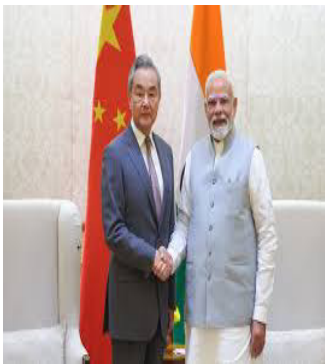
इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काटज ने शुक्रवार को गाजा सिटी को पूरी तरह तबाह करने की धमकी दी। काटज ने कहा, अगर हमास इजराइल की शर्तें नहीं मानेगा तो उसे अंजाम भुगतना होगा। यह बयान ऐसे समय में आया जब एक दिन पहले काटज ने गाजा सिटी पर कब्जे के लिए सेना को अनुमति दी थी। काटज ने सोशल मीडिया

प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा— गाजा का हाल राफा और बैत हनून शहरों जैसा हो सकता है, जो मलबे मतब्दील चुके हैं। ठीक जैसा मैंने वादा किया था। दरअसल, इजराइल ने जंग खत्म करने के बदले सभी कैदियों की एक साथ रिहाई और हमास के पूरी तरह से हथियार डालने समेत 5 शर्तें रखी थी।

जंग खत्म करने के बदले 5 शर्तें रखी — हमास पूरी तरह हथियार डाले। बचे हुए सभी कैदियों की एक साथ रिहाई। गाजा से सैन्य ताकतों का खाल्ता। गाजा पर इजराइल का सुरक्षा नियंत्रण। गाजा में ऐसा ऑप्शनल नागरिक प्रशासन बनाना, जो न तो हमास हो और न ही फिलिस्तीनी प्राधिकरण।

अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ भारत के सपोर्ट में चीन , चीनी राजदुत बोले चुप रहे तो दबंगई बढेगी।

चीनी राजदुत ने भारत के समर्थन में कहा ,भारत-चीन प्रतिद्वंद्वी नहीं साझेदार है



चीन के राजदूत शू फीहोंग ने गुरुवार को भारत पर लगाए गए 50: अमेरिकी टैरिफ की निंदा की। उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित एक प्रोग्राम में कहा कि चीन इसका कड़ा विरोध करता है। चुप रहने से दबंगई को बढ़ावा मिलता है। चीन भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। फीहोंग ने भारत और चीन के बीच

रणनीतिकभरोसे और सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देश प्रतिद्वंद्वी नहीं,बल्कि साझेदार हैं और मतभेदों को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए।चीनी राजदूत ने कहा— भारत और चीन को आपसी संदेह से बचना चाहिए और रणनीतिक भरोसे को बढ़ाना चाहिए। दोनों देशों के लिए एकजुटता और सहयोग ही साझा विकास का रास्ता है। अमेरिका ने भारत कुल 50: टैरिफ लगाया है। इसमें से एक्स्ट्रा 25: टैरिफ रूसी तेल खरीदने की वजह से लगाया है, जो 27 अगस्त से लागू होगा। अमेरिका का कहना है कि भारत के रूसी तेल खरीदने की वजह से रूस को यूक्रेन जंग में मदद मिल रही है।फीहोंग बोले— भारत-चीन दोस्ती दुनिया के लिए फायदेमंद — फीहोंग ने ग्लोबल हालात पर

कहा कि दुनिया इस समय बड़े बदलावों से गुजर रही है और ऐसे में भारत-चीन रिश्तों का महत्व और बढ़ गया है। उन्होंने कहा— भारत और चीन एशिया की आर्थिक प्रगति के दो इंजन हैं। हमारी दोस्ती न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद है। फीहोंग ने कहा कि एससीओ समिट के लिए पीएम मोदी चीन यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति देगी। यह विजिट 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के तियानजिन में होगी। हाल ही में चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने पीएम मोदी से मुलाकात कर उन्हें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का निमंत्रण सौंपा था। मोदी ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वह शी जिनपिंग से तियानजिन में मुलाकात के लिए उत्सुक हैं।

भारत से रिश्ते बिगाडना अमेरिका की बडी गलती , भरोसा टुटा तो पच्चीस साल की मेहनत खराब - निक्की हेली।

निक्की ने न्यूजटीक मैगजीन में लिखे अपने अर्टिकल मे कहा भारत से रिश्ते बिगाडना पच्चीस साल की मेहनत खराब करने जैसा ।



संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली ने भारत से संबंधों को लेकर ट्रम्प प्रशासन को चेतावनी दी है। न्यूजवीक मैगजीन में लिखे अपने आर्टिकल में निक्की कहा कि अगर भारत के साथ 25 साल में बना भरोसा टूटता है, तो यह एक रणनीतिक गलती होगी। निक्की ने यह आर्टिकल ट्रम्प के भारत पर लगाए गए 50: टैरिफ और उसके दोनों देशों के संबंध पर असर के बारे में लिखा है। उन्होंने ट्रम्प प्रशासन को सलाह दी है कि वह भारत को एक और लोकतांत्रिक साझेदार माने। भारत-अमेरिका

के रास्ते अलग लेकिन मंजिल एक — निक्की ने आर्टिकल की शुरुआत रीगन और इंदिरा गांधी के बीच 43 साल पहले हुए एक मुलाकात से की है। उन्होंने लिखा— जुलाई 1982 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनल्ड रीगन ने व्हाइट हाउस में भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए डिनर रखा था। उस समय उन्होंने कहा था कि भारत और अमेरिका दो आजाद देश हैं। कभी-कभी हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है। लेकिन चार दशक बाद आज अमेरिका-भारत संबंध मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं।

निक्की बोलीं— भारत पर टैरिफ लगाया, चीन पर नहीं — निक्की ने अपने आर्टिकल में आगे लिखा कि चीन पर रूस से तेल खरीदने के बावजूद कोई प्रतिबंध नहीं है, जबकि भारत पर अमेरिकी टैरिफ लगाए जा रहे हैं। हेली के मुताबिक यह दिखाता है कि अमेरिका— भारत रिश्तों पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। हेली ने कहा कि भारत ही वह देश है जो एशिया में चीन की बढ़ती ताकत को बैलेंस कर सकता है। पूर्व राजदूत ने यह भी कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही जापान को पीछे छोड़ देगा। भारत का यह उभार चीन की महत्वाकांक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक विवाद को अगर लंबे समय के लिए बढ़ाया गया, तो चीन इसका फायदा उठा लेगा। उन्होंने सुझाव दिया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सीधे पीएम मोदी से बात करें और रिश्तों को फिर से पटरी पर लाएं

खबरों के लिए लॉगिन करें

https://sbpatra.in/